वस्तुएं	वर्ष		
	1993-94	1994-95	1995-96
खाद्य तेल	0.40	0.50	0.20
मिट्टी का तेल	152.53	154.00	156.47
सॉफ्ट कोक	—	—	—

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम की समीक्षा किया जाना

1662. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए चलाये जा रहे स्वरोजगार कार्यक्रम की गत दो वर्षों के दौरान तथा अक्टूबर, 1996 तक समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए कितने बेरोजगार युवकों से आवेदन प्राप्त हुए, कितने मामलों में ऋण स्वीकृत किए गए तथा कितने मामलों में वास्तविक रूप से भुगतान किया गया है और इस संबंध में रज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलि मारन): (क) जी, हां।

(ख) नवीनतम समीक्षा अगस्त, 1996 में की गयी थी। प्रगति की निगरानी की गयी थी और स्वीकृतियों और संवितरणों को तेज करने, बैंकों को समर्थक ऋणाधार न मागने के निर्देशों को दोहराने, लाभभोगियों के प्रशिक्षण को तेज करने आदि के लिए कदम उठाये गये।

(ग) राज्यवार, ऋण हेतु बेरोजगार युवकों से प्राप्त आवेदनों की संख्या, जिला उद्योग केन्द्रों/उद्योग निदेशालय द्वारा बैंकों को सिफारिश किये गये आवेदनों की संख्या, वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा सितम्बर, 1996 तक वर्ष 1996-97 के लिए स्वीकृत और निपटान किये गये मामलों की संख्याएं अनुबंध की गयी हैं। [देखिए परिशिष्ट 179, अनुपत्र सं० 35]

Policy on fully owned untis by MNCs

1663. SHRI JANARDHANA POOJARY:
SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item which appeared in the 'Times of India' dated the 12th October, 1996 under the caption "Move for policy on fully owned units by MNCs is off"

(b) if so, the details of the decision taken; and

(c) the reasons for change of this policy?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) No fresh policy guidelines have been issued on fully-owned units by MNCs. Therefore, there is no question of this move having been put off. However, the foreign investment policy is constantly kept under review to make it more investor-friendly and dynamic with the objective of increasing Foreign Direct Investment into the country particularly, in the priority sectors including infrastructure. The Government announces its decision on the policy initiatives etc., through Press Notes/Releases as and when such decisions are taken.